

Title : Shri Prabhunath Singh called the attention of the Minister of Rural Development to the need to look into the progress of implementation of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna in Bihar and steps taken by the Government in this regard.

### Need to look into the progress of implementation of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana in Bihar and steps taken by the Government in this regard

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें।

" बिहार में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच किए जाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम। "

MR. SPEAKER: You can lay the Statement.

**ग्रामीण विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

\*प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 969 पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी कुल लंबाई 2219 किलोमीटर एवं लागत 452 करोड़ रुपये है। इसके विरुद्ध कुल 359.90 करोड़ रुपये विमुक्त किये जा चुके हैं। अब तक 463 पथ, जिनकी लंबाई 1157.90 कि.मी. है, पूर्ण किये जा चुके हैं और 298.05 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

वर्ष 2004 में बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय एजेंसियों को दी गयी। तदनुसार केन्द्रीय एजेंसियां यथा इस्कॉन, एनबीसीसी, एनएचपीसी, एनपीसीसी एवं सीपीडब्ल्यूडी को कार्यान्वयन हेतु चिन्हित कर राज्य के विभिन्न जिले संबद्ध किए गए।

केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् हैं -

अब तक 252 पथों का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी कुल लागत 723 करोड़ रुपये एवं लंबाई 2391 कि.मी. है।

34.29 कि.मी. लंबाई के 4 पथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

1208.77 कि.मी. के 130 पथों का निर्माण कार्य जारी है।

521 कि.मी. लंबाई के 65 पथों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

---

\* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 3200/2005

515 कि.मी. लंबाई के 52 पथों की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है।

2827 कि.मी. लंबाई के 328 पथों की डीपीआर बनाने एवं संवीक्षा की कार्यवाही जारी है।

इन केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि प्रथम दो चरणों में लिए गए पथों की अवशेष लंबाई का पूरक प्रस्ताव भेजें।

राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि त्वरित गति से कोरनेटवर्क, सीएनसीपीएल एवं सीयूपीएल तैयार कर प्रस्तुत करें। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत निर्माण के अंतर्गत 9956 से अधिक आबादी वाली योग्य बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा 9295 कि.मी. पथों के सुदृढीकरण के लिए कार्य योजना बनाकर समर्पित करें।

MR. SPEAKER: Please do not raise hands. If anybody raises hands, I am not going to allow any second Member.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have already said that whose names are there, they will only be allowed.

...(Interruptions)

**अध्यक्ष महोदय :** हम जरूर ध्यान रखेंगे। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री सड़क योजना शतप्रतिशत केन्द्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रथम चरण में एक हजार की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पहाड़ी इलाकों में 500 की आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ना है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के कुल 1907 गांवों का चयन किया गया है जिसमें 968 सड़कों की संख्या है तथा लंबाई 2220 किलोमीटर है। हम खंडवार पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 2222 कि.मी. सड़क में से अब तक बिहार में कितने कि.मी. सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है और उस पर कितनी राशि आवंटित की गई ? जो जवाब माननीय मंत्री जी का आया है, जो आज का आपका जवाब है और जो पहले आपने कितना भेजी है, हमें लगता है कि आंकड़ों में थोड़ा अंतर पड़ रहा है। आप इन आंकड़ों को एक बार देख लें और देखकर स्पष्ट रूप से बताएं कि कितनी राशि अब तक आपने स्वीकृत की और कितनी राशि विमुक्त की ? हम माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहेंगे कि यह योजना 2000-2001 से शुरू की गई और बिहार में ५

1थम फेज में 298 सड़कों का चयन किया गया जिसकी लम्बाई लगभग 811.66 कि.मी. है जिसमें 149.9 करोड़ रुपया विमुक्त किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2004 तक 143 सड़क यानी 413 कि.मी. सड़क का निर्माण हुआ जिसे लगभग 50 प्रतिशत की उपलब्धि माना जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसे 50 प्रतिशत की उपलब्धि कहा गया है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ दूसरी ही है।

माननीय मंत्री जी, हम आपकी सूचना के लिए यह बात बता रहे हैं। हम आप पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं कि प्रथम चरण में भी आपने जो राशि शुरू की थी, जो कार्य शुरू किये गये थे, जो निविदा निकली थी जिसमें पचास प्रतिशत की उपलब्धि का आपने ब्योरा दिया है, उसमें से बहुत सारे काम अभी तक पूरा नहीं किये गये हैं और काफी सारा काम अभी अधूरा है। जब काम अधूरा है तब आप इसे उपलब्धता कैसे मान सकते हैं ? जो आपने जांच टीम बनाई थी कि जो सेवानिवृत्त इंजीनियर थे, जो देश भर के लोगों को बुलाकर उसमें सम्मिलित किया था कि ये लोग जांच करेंगे और जांच करके क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रतिवेदन देंगे, जिसके आधार पर केन्द्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी लेकिन जो आपके इंजीनियर गये, माननीय मंत्री जी, इसे आप आरोप-प्रत्यारोप के रूप में नहीं लीजिएगा, जो रिटायर लोग थे, जो बेरोजगार हो गये थे, उनको आपने एक नयी नौकरी, एक नया रोजगार देने का काम किया। जो नौकरी में हैं, जिन्हें अपने निलम्बन का डर है, जिन्हें कार्रवाई का डर है, जब आप उनसे कोई काम नहीं करा सकते हैं तो जो लोग सेवानिवृत्त हो गये हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जो रोजी-रोटी के लिए आपके यहां आ गये हैं, उनसे आप कितना निपक्ष और सही काम की उम्मीद कर सकते हैं ? हमारा यह मानना है कि जो लोग गये, उसकी जांच वे सही तरीके से नहीं कर पाए और जिसके कारण आपकी क्वालिटी में सुधार नहीं हो पाया है। दूसरे, हम यह कहना चाहेंगे कि आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और क्वालिटी के संबंध में अगर आप बिहार की सड़कों की जांच करने के लिए जो आपकी कमेटी गई है और जो क्वालिटी का प्रतिवेदन आया है, उस प्रतिवेदन के आधार पर आप यह बताइए कि किन-किन जगहों पर आपके प्राक्कलन के आधार पर क्वालिटी सही पाई गई है और आपके प्राक्कलन के आधार पर काम पाये गये हैं और कितनी जगहों पर आपके प्राक्कलन के अनुसार क्वालिटी के काम नहीं हुए हैं ? जहां क्वालिटी के अनुसार काम नहीं हुए हैं, वहां संबंधित पदाधिकारियों या उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या राज्य सरकार से आपने कोई परामर्श किया है ? क्या आपने उनको कोई दिशानिर्देश दिया है ? अगर आपने दिशानिर्देश दिया है तो इस संबंध में बताइए कि अब तक उन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई है और 2002-03 में जो आपने राशि आवंटित की थी, उस राशि की उपलब्धि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 14 प्रतिशत बताई जाती है। हम यह जानना चाहते हैं कि सन् 2000-2001, 2002-2003 में कुल मिलाकर जो बिहार की सड़कें स्वीकृत थीं और जो स्वीकृति के बाद भी राशि विमुक्त नहीं की थी, क्या उस राशि को आप विमुक्त करना चाहेंगे ? जो बाकी सड़क है, उसे क्या आप पूरा कराना चाहेंगे ? इसी के साथ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर ये आंकड़े सही हैं तो 2003-04 में बिहार की एक कि.मी. सड़क की भी आपने स्वीकृति नहीं की है। जब स्वीकृति आपने नहीं की है तो पैसा देने का कहीं से कोई स्वाल नहीं उठता है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि 2003-04 में जो बिहार का हिस्सा बना, जो सड़कें आप किश्तवाइज कर रहे हैं, कारण कि आपने कुल सड़कों की संख्या और लम्बाई का आपने आकलन करया है, उसके आधार पर जो 2003-04 का जो बिहार का हिस्सा बनता है, उस राशि को क्या आप बिहार के लिए विमुक्त करेंगे ? क्या आप बिहार में उन सड़कों का निर्माण कराने का काम करेंगे ?

महोदय, जहां तक वर्ष 2004-05 और 2005-06 का स्वाल है, यह बात सत्य है कि आपके कार्यालय में एक बैठक हुई थी जिसमें आपने हम लोगों को भी आमन्त्रित किया था। हम लोग लोकसभा के अन्दर और बाहर भी बराबर कहते रहे हैं कि बिहार की एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए आप केन्द्रीय एजेंसी से काम करवाइए और उसमें यह सहमति बनी थी कि केन्द्रीय एजेंसी से करवाया जाए। आपने जवाब में भी लिखा है कि हमने केन्द्रीय एजेंसी के जिम्मे ये काम दिये हुए हैं और उसके लिए आपने कहीं-कहीं पर निविदाएं भी आमन्त्रित की हैं। आपने एक पत्र का हवाला एक प्रश्न के उत्तर में देते हुए कहा था कि हम इनको पत्र भेजते हैं, वे पढ़ते नहीं हैं और जमीनी हकीकत को जानते नहीं हैं, इसलिए मैं उस पत्र का जिक्र करना चाहता हूँ। हमने इस पत्र को पढ़ा है।

**अध्यक्ष महोदय :** अपनी बात को इतना लम्बा करने से कैसे काम चलेगा।

**श्री प्रमुनाथ सिंह :** महोदय, मैं बिल्कुल प्वाइंटेड बात कह रहा हूँ।

मंत्री महोदय ने हमें जो पत्र भेजा है, उसमें केवल तीन जिलों की सूची भेजी गयी है, उसमें पूरे बिहार की सूची नहीं है। इन तीन जिलों के मिलाकर चार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, जिनमें से एक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से श्री साधु यादव जी आते हैं, तीसरे निर्वाचन क्षेत्र से शहाबुद्दीन साहब आते हैं और चौथा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। आप अपनी सूची देख लीजिए, इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह ठीक नहीं है और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें से पहले तीन निर्वाचन क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं, उनके लिए आपने निविदाएं आमन्त्रित की हैं, उन पर अद्यतन निर्माण की कार्यवाही की है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में आपने लिखा है कि फॉर्मल स्वीकृति के बाद ही इस पर कार्यवाही होगी और सर्व प्रोग्रेस में है। आपकी नीयत क्या है? क्या आप इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से सड़कों का निर्माण कराएंगे कि जिन इलाकों में आपके दल के सांसद हों, उनमें सड़कों का निर्माण होना चाहिए और जहां आपके दल के सांसद नहीं हों, वहां सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए?

अध्यक्ष जी, यह माननीय मंत्री जी की चिट्ठी है, मेरी नहीं और अगर आपका आदेश हो तो मैं इसे सदन के पटल पर रख दूंगा। चूंकि उन्होंने इस चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा था इन्होंने हमें चिट्ठी भेजी है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक निपक्ष तरीके से बिहार में सड़कों के विकास के लिए प्रयास कीजिए। चूंकि बिहार के विकास के बारे में आपने कहा था कि वर्ष 2009 तक बिहार की सड़कों का आप इस ढंग से विकास कराएंगे कि बिहार भी अगली पंक्ति में खड़ा होगा। लेकिन कैसे खड़ा होगा यदि आप इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से काम करेंगे? जो मीटिंग हुई थी उसमें यह सहमति बनी थी कि पीडब्ल्यूडी की लम्बी सड़कों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 की आबादी वाले इलाके के लोगों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ेंगे। उस उद्देश्य को आप कैसे पूरा करेंगे?

दूसरी बात यह है कि अगर केन्द्रीय एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कराती है तो उस स्थिति में, चूंकि अब राज्य में काम करने वाली सरकार हो गयी है, क्या आप उस पैसे को राज्य सरकार को देंगे ताकि सही समय पर इन सड़कों का निर्माण किया जा सके। साथ ही इसकी मॉनीटरिंग और जांच के लिए आपने क्या-क्या तरीके निकाले हैं, इन तरीकों पर कृपया विस्तार से चर्चा कीजिए?

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार मानता हूँ कि आपने जनहित के स्वाल पर ध्यानार्कण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देने की कृपा की है। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता के हित की उन्होंने चिन्ता की है और वह उत्सुक हैं कि लोगों की कठिनाई जल्दी से दूर हो एवं यातायात की समस्या हल हो, सड़कें वहां बनें। लेकिन महोदय, माननीय सदस्य ने अन्त में यह जो कहा कि भेदभाव हुआ हुआ है और हो रहा है, यह कहना निराधार और पूर्वाग्रहग्रस्त है।

**श्री प्रमुनाथ सिंह :** मैंने तो आपकी ही चिट्ठी पढ़ी है।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** वह चिट्ठी तो हमने आपको जानकारी देने के लिए लिखी थी और केवल आपको ही नहीं बिहार के सभी माननीय सदस्यों को इस चिट्ठी के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी हमने दी है।

महोदय, कोई भेदभाव नहीं है। (व्यवधान)

**श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) :** ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** आपको भी पत्र दिया गया है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इस तरह से आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसा मत करें। Nothing will be recorded.

(Interruptions)\*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** हमने सभी माननीय सदस्यों को पत्र दिया है। हमारे पास सूबूत है उनकी रिसीविंग का। अगर कोई माननीय सदस्य चुनौती देता है तो मैं, वह चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैंने सभी सदस्यों को पत्र दिए हैं। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record. The statement of any hon. Member speaking without my permission will not be recorded.

(Interruptions)\*

MR. SPEAKER: Do not do this. Nobody should interrupt.

...(Interruptions)

**अध्यक्ष महोदय :** थोड़ी छवि ठीक करें।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** सर्वप्रथम चीज है ट्रांसपेरेंसी की, कि सब लोग जानें। इसीलिए हमने सभी माननीय सदस्यों के साथ लिखा-पढ़ी की और उन्हें अद्यतन स्थिति की जानकारी देते रहते हैं। मैंने तीन बार संसद सदस्यों के साथ बैठक की है और बिहार के माननीय सदस्यों के साथ भी की है। अब हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया राशि का कि पांच-छः वॉ से बिहार को उसका हिस्सा नहीं मिला। इस वॉ बिहार का हिस्सा 1082 करोड़ रुपए था, जिसमें से अभी तक 1141 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। अभी तक एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट 294 करोड़ रुपए की है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस के हिसाब से यह स्थिति है। फिजीकल प्रोग्रेस के हिसाब से अभी तक हमने 4498 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी है। (व्यवधान)

\* Not Recorded.

MR. SPEAKER: I will have to request hon. Members not to interrupt.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: What are you doing here?

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: This is very unfortunate that the Speaker of Lok Sabha has to request Members to keep quiet. You should all think what you are doing.

...(Interruptions)

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** मैंने अपने लिखित स्टेटमेंट में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। 2219 किलोमीटर सड़क की लागत 452 करोड़ रुपए है। उसके लिए 359 करोड़ रुपए विमुक्त किए जा चुके हैं। 463 पथों की लम्बाई 1197 किलोमीटर है, उसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

**श्री लाल मुनी चौबे :** मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं सदन से वाकआउट करता हूँ।

**12.28 hrs.** (Shri Lal Muni Choubey then left the House)

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** उस पर 298 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। उसके बाद अब तक 252 पथों का कार्य निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसकी कुल लागत 723 करोड़ रुपए है और लम्बाई 2391 किलोमीटर है। 34.29 किलोमीटर लम्बे चार पथों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 1208 किलोमीटर के 130 पथों का निर्माण कार्य जारी है। 521 किलोमीटर लम्बाई के 65 पथों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। 515 किलोमीटर के 52 पथों की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है। 2827 किलोमीटर लम्बाई के 328 पथों की डीपीआर बनाने सम्बन्धी समीक्षा की कार्यवाही चल रही है और काम तेजी से चल रहा है। इसलिए अद्यतन यह स्थिति है।

माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र का सवाल उठाया है। हमने उन्हें यही कहा था कि देश के सभी जिलों में अच्छे ठेकेदारों की कमी है। इसलिए टेंडर कम आ रहे हैं। छपरा में दस-पन्द्रह दिन पहले एक भी टेंडर नहीं डाला गया, जबकि तीन-तीन बार एक्सटेंशन दिया गया। कल की रिपोर्ट है कि दो किस्तों में टेंडर डाला गया है और दो सड़कों का टेंडर अर्बाई किया जा चुका है।

महोदय, इनका क्षेत्र दो जिलों में पड़ता है। सीवान जिले में अभी तक तीन-तीन बार एक्सटेंशन हुआ टेंडर का, लेकिन किसी का टेंडर नहीं डाला गया। इसीलिए हमने माननीय सदस्य से सहायता की अपेक्षा की थी कि टेंडर दिया जा रहा है, लेकिन किसी के द्वारा टेंडर नहीं डाला जा रहा है। इसलिए कृपा करके छानबीन की जाए कि क्या बात है और क्या बात होने से वहां टेंडर डाला जा सकता है। **â€** (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** बीच में न टोकें। मंत्री जी अच्छा भाण दे रहे हैं।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** जहां तक क्वालिटी की बात है, तो पहले तीन स्तर पर क्वालिटी की देखरेख होती थी। पहले राज्य सरकार द्वारा होती थी। दो स्तर पर सड़कों की क्वालिटी की जांच करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। तीसरे स्तर पर यहां सेंटर से नेशनल लेवल मॉनिटरिंग होती है। जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको इसमें रखा गया है। अगर कोई शिकायत होती है तो जांच कराई जाती है। हमने निर्देश दिया है कि जो सड़कें बन रही हैं उनकी शुरु में, मध्य में और अंत में, तीन बार जांच हो, जिसे अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जांच हो सके। इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले जो टेक-ऑफ नहीं लिया था, अब काम टेक-ऑफ ले रहा है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी सरकार आ गयी है। हमने कहा कि जो पहले की अधूरी सड़कें हैं। **â€** (व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** हमने कहा है कि काम करने वाली सरकार आई है।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** आपको भरोसा है लेकिन तुरंत पता चल जाएगा कि कितना काम करने वाली सरकार है।

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, I am sorry. I gave you full opportunity to speak, and the hon. Minister has also given his reply.

...(Interruptions)

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** हमने कहा है कि पहले की जो सड़कें ली गयी हैं उनका मिंसिंग लिंक बचा हुआ है उसकी तुरंत डीपीआर बनाएं और राज्य सरकार चाहे तो अपने से उन्हें पूरा करे। **â€** (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, I am sorry. I cannot allow this to go on like this.

...(Interruptions)

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** हमारा कहना है कि जो भारत निर्माण की योजनाएं हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की कि चार वर्षों में 48,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे यानी 12,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेंगे। पुरानी सरकार तो ढाई हजार करोड़ रुपया सालाना खर्च करती थी। हमारा बजट 48,000 करोड़ रुपये का है। अगले साल 9 हजार करोड़ रुपये का बजट है। वह सरकार ढाई हजार करोड़ रुपया सालाना खर्च नहीं कर पाती थी वहीं हम 12,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेंगे यानी पांच गुना अधिक खर्च करेंगे। हमने देश के सभी राज्यों के सचिवों की दो बार बैठकें की हैं। हमने राज्यों सरकारों से कहा है कि वे अपनी खर्च करने की क्षमता बढ़ाएं क्योंकि चार वर्षों के अंदर हजार की आबादी वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। पहाड़ी और ट्राइबल्स एरिया की पांच सौ की आबादी तक के गांव को चार वर्षों में ऑल वैदर रोड से जोड़ने की योजना है। हमें भारत निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करना है। महोदय, मैं आपसे और माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी तीन महीने में एक बार जरूर बैठक करें और सभी कामों की मॉनिटरिंग करें और इस काम के लिए हमें प्रोत्साहित करें, जिसे माननीय सदस्यों, राज्य सरकारों और पंचायती राज सहयोग से हम इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा कर सकें।

इसमें माननीय सदस्यों को पूरी अहमियत दी गयी है। माननीय सदस्यों को हमने कहा है कि उनकी पूरी सूची दी गयी है और कहा गया है कि आपको निर्देश मानना पड़ेगा। नहीं मानने पर बताना पड़ेगा कि वह कानून में है या नहीं। हमने कहा है कि माननीय सदस्य ही उस काम का शिलान्यास करें, शुरुआत करें, उसका उद्घाटन करें। इस तरह से माननीय सदस्यों को पूरी अहमियत दी गयी है। इस तरह से माननीय सदस्यों का सहयोग होगा और जनता का काम होगा। **â€** (व्यवधान)

MR. SPEAKER: It cannot go on like this.

...(Interruptions)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें कहने दिया जाए।

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please sit down. I have already allowed your matter to be raised in the House.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions)\*. **â€**

\* Not Recorded.

MR. SPEAKER: Shri Devendra Prasad Yadav.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please allow me to regulate the proceedings of this House. Please sit down.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, हम आपसे अपील करते हैं कि आप सहयोग करें। Do not record it. Nothing will be recorded.

(Interruptions)\*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। I appeal all of you to please co-operate with the Chair.

...(Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह : मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हो गये हैं।

MR. SPEAKER: I would not allow him to speak

...(Interruptions)

---

---

\* Not Recorded.